गुजरात में विकास केन्द्र

2325. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विकास केन्द्रों को वर्तमान में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जाने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात में विकास केन्द्रों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिसके परिणामस्वरूप ये केन्द्र समुचित तरह से कार्य नही कर रहे हैं; और

(ग) किस-किस जिले में ये केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा 1988 में घोषित "विकास केन्द्र" योजना के अधीन विकास केन्द्रों में बिजली, पानी, दूरसंचार, बैंकिंग आदि आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगी ताकि इन क्षेत्रों में उद्योगों को आकृष्ट किया जा सके ।

चुने हुए केन्द्रों के बारे में राज्य सरकारों को व्यापक परियोजना रिपोर्ट भेजनी होती हैं जिनका मूल्यांकन और अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है । परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित होने के बाद केन्द्रीय सहायता दी जाती है और तदुपरान्त राज्य सरकारों द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जाता है । गुजरात के तीनों विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित हो चुकी है और केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रत्येक विकास केन्द्र को 50 लाख रुपए की राशि दे दी गई है ।

(ग) विकास केन्द्रों के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार गुजरात को 3 विकास केन्द्र अवंटित किये गये है । ये है—कच्छ जिले का गांधीधाम, बनासकांठा का पालमकपुर और भड़ौच का वागरा ।

Review of appointment of Chief Executives

2326. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the present position of the review cases relating to appointment of Chief Executives made by the then Government during election days;

(b) whether it is a fact that continuance of such Chief Executives has already damaged concerned public sectors immensely; and

(c) if so, the details thereof and performances achieved during their period of stay in each Public Sector Undertaking?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRIES AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Review in respect of 18 out of a total of 21 appointments of Chief Executives made during the election period has been completed. The remaining 3 cases are at different stages of review.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Setting up of Industries in Bihar

2327. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received any new proposals for setting up of new Industrial units in Bihar after the libralised Industrial Policy of Government was announced;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government propose to give package of incentives with cooperation of Government of Bihar to the Industrialists for setting up of Industries in Bihar;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) what other steps Government have taken for the rapid Industrialisation of Bihar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMSNT) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) After the announcement of the new Industrial Policy in July, 1991, 42 Industrial Entrepreneurs Memoranda have been field by entrepreneurs for setting up of Industries in Bihar. In addition, 8 applications for grant of Letter of Intent (LOI) have been received against which one LOI has been granted; 4 rejected/disposed and 3 are under process.

(c) to (e) The responsibility for developing industries in a State rests primarily with the State Govt. The Central Govt. supplements the efforts of the State Govt. Ministry of Industry have approved six Growth Centres for creating infrastructural facilities for the speedy industial development of Bihar State.

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2328. **श्री राजूभाई ए० परमार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अप्रैल, 1992 तक कुल कितनी पूंजी लगाई जा चुकी थी ;

(ख) इन उपक्रमों के उत्पादन से प्रतिवर्ष कितना लाभ/घाटा होता है; और प्रत्येक उपक्रम में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ग) गुजरात में स्थित उन केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें केन्द्रीय सरकार और अधिक पूंजी लगाना चाहती है और निर्माणाधीन केन्द्रीय परियोजनायें कौन-कौन सी हैं और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है ;

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केवल 31-3-1991 तक की जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे दो उद्यम हैं, जिनके पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य में स्थित हैं । वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक उपक्रम में सामान्य शेयरों और ऋणों के रूप में किया गया कुल पूंजीनिवेश, शुद्ध लाभ/हानि तथा कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	सामान्य शेयरों तथा ऋणों के रूप में किया पूंजी निवेश (करोड़ रुपयों में)	शुद्ध लाभ/ हानि (करोड़ रुपयों में)	कर्मचारियों की संख्या
1.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लि०	1402	57	10037
2.	नेशनल फर्टिलाइजर्स (गुजरात) लि०	210	(-)22	15903